

મહિલાયાત્રીકા બૈગ ગાયબ પુલિસને એક ઘંટેમાં કિયા બરામદ



શહ ટાઇસ સંવાદદાતા

બુધવાર દોષારી, ચંદ્રોસી નિવાસી મહિલા કુસુમ અપણે પરિવાર કે બચ્ચોને કાથા ચંદ્રોસી જાન કે લિએ એક ઈ રિસ્ક્સ મેં હોય અને બસ સ્ટેન્ડ પર ઉત્તર ગઈ। ઈ રિસ્ક્સ સાં ડરને કે બાદ મહિલા કો બાદ આયા કે ઉસકી બૈગ ઈ રિસ્ક્સ મેં હોય રહ્યા હૈ। મહિલા યાત્રી કુસુમ ને ઇસીંસી સુચના વિલારી થાને મેં હોય।

મહિલા કી સુચના પર થાને કે દરેગા સુનીલ કુમાર ને તલ્કાન પ્રયાસ કરે એક ઈંટે મેં ડ્રિવિંગ ચાલક કે હુલિયા કી જાનકારી કરે ઉસ

મહિલા કા બૈગ બરામદ કર લિયા ઔર મહિલા યાત્રી કો સૌંપ દિયા

પુલિસની સક્રિયતા કો લોકર લોગોને પ્રશંસા કરી।

ਹਕੀਕਤ ਨੇ ਖਾਸ ਮੁਦੇ

भाजपा और कांग्रेस समत चुनाव भन्न राजनीतिक दलों न भल हो अतीत में इलेक्ट्रॉनिक बोटिंग मशीनों के बारे में शिकायतें उठाई हैं, लेकिन प्रशासनिक और तकनीकी सुरक्षा उपायों के मद्देनजर उनमें से कई जांच में खरो नहीं उतरवाए। कांग्रेस ने अब चुनावी प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित कर लिया है तथा ज्यादा मौलिक मुद्दों को उठाया है, जिन पर अलग से विचार किए जाने की जरूरत है। तात्पत्र चलें कि लोकसभा में विधायिकों ने नेता राहुल गांधी को उठाया है, जिन पर अलग से विचार किए जाने की जरूरत है। महाराष्ट्र में 2024 के विधानसभा चुनावों में जो कुछ हुआ, उसके आधार पर चुनाव संचालन को लेकर परेशान करने वाले सवाल उठाए हैं। इसमें हकीकत में कुछ खास मुद्दे हैं, जिसे आम चुनाव और विधानसभा चुनावों के बीच मतदाता सूची में सूचीबद्ध मतदाताओं की संख्या में असामान्य बढ़ि, मतदान के दिन शाम 5 बजे के बाद मतदान प्रतिशत में वृद्धि तथा मतदान प्रक्रिया के सीसीटीवी फूटेज तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के बासे केंद्र द्वारा चुनाव संचालन नियम, 1961 में संशोधन किया जाना। गांधी ने निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की उस प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया है, जिसमें केंद्र सरकार ने 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने से इन्कार कर दिया है। उक्त फैसले में निर्वाचन आयुक्तों का चयन करने वाले पैनल के एक हिस्से के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीशों ने शामिल करने की सिफारिश की गई थी। जिन राज्यों में आम चुनाव और विधानसभा चुनाव निकट थे, वहां पंजीकृत मतदाताओं की संख्या के बारे में किए एक शुरुआती विश्लेषण से पता चला कि विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं की संख्या में तेज उत्ताल के उदाहरण खड़ थे। जहां विधानसभा चुनावों से पहले जो गए नये मतदाताओं की संख्या ज्यादा थी, आम चुनावों के बाद मात्र छह महीनों में 39 लाख से ज्यादा मतदाता जुड़े, वहां 2014 में भी इसी किस्म की बढ़ोतारी देखी गई थी। लगभग चार मिलियन मतदाताओं की बढ़ोतारी एक बड़ी तादाद है और भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को सत्यापन के लिए मतदाता सूची से संबंधित मशीन द्वारा पठनीय आंकड़ों को सक्रियतापूर्वक जारी करना चाहिए। इस आरोप के संबंध में कि शाम 5 बजे के बाद मतदान प्रतिशत में बढ़ोतारी असामान्य थी, यह तर्क सही नहीं है। यह मतदान के तात्कालिक (प्रार्थि. जनल) आंकड़ों पर आधारित है और ईसीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र में शाम 5 बजे के बाद मतदान में कोई उल्लेखनीय बढ़ोतारी नहीं हुई। ईसीआई द्वारा एक एप के जरिये साझा किए गए मतदान प्रतिशत के तात्कालिक आंकड़े पूरी तरह से सटीक नहीं होते हैं, क्योंकि ये चुनाव के दौरान संख्याओं की हाथ से की गई (मैनुअल) प्रविटि पर निर्भर होते हैं और मशीन की सटीक गणना से तुलना करने पर इनमें विचारित तरफ से अंतर होते हैं। एप्प सर्वप्रथम 17 जून से उपयोग के लिए उपलब्ध हो गया है।

प्रधानमंत्री जोटी सर्वदलीय बैठक की

अध्यक्षता कब करेंगे



32 दरेंगों की यात्रा से लोटे से 7 डेलिगेशन के 51 सासंदों से पीएस का मिलना टीक है, यह उनका विशेषाधिकार है और ये कोई आशयवाची की बात नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ आसान सवाल हैं, कि पीएस इन सवालों का जवाब दें, प्रधानमंत्री मोदी सर्वदलीय बैठकी की अध्यक्षता कब करेंगे, परिवर्तीयों के सासंदों से नहीं, बल्कि नेताओं से कब मिलेंगे, पहलगाम आतंकी हमले के बाद समझे आई भौतिरी और बाहरी सुरक्षा चुनौतियों पर इन नेताओं को कब विश्वास में लेंगे, कारगिल सुझ के बाद हमारे पास एक कारगिल समीक्षा समिति थी। यवा सिंगापुर में सौडीईस के खुलासे के बाद भी ऐसी ही कावदारी होगी, यवा समीक्षा होगी, यवा कोई विश्वासण होगा, यवा कोई रिपोर्ट होगी।

-जयराम रमेश, कांग्रेस महासचिव

ह र वर्ष 12 जून को विश्व बात श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरूआत वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बच्चों को मजदूरी से मुक्त करने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से की थी। वर्ष 2025 में इस दिवस की थीम है प्रगति स्पृह है लेकिन अभी और काम किया

जाना बाकी है - आइए प्रयासों में तेजी लाएं। यह थीम आज के समय की जमीनी सच्चाइ को बखूबी

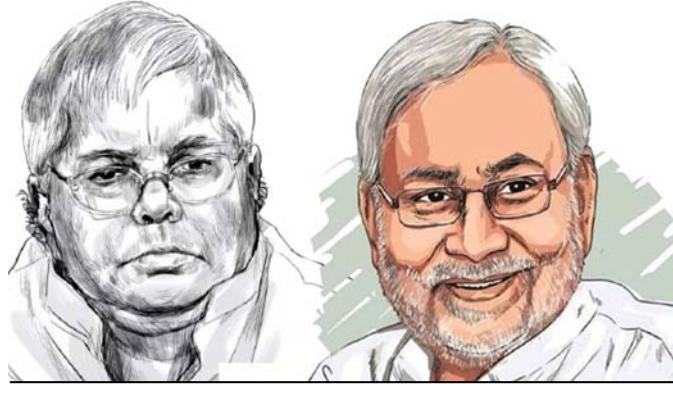
दर्शाती है क्योंकि वैश्वक स्तर पर लाखों बच्चे अब भी उस अंधेरे दलदल में फँसे हैं, जिसे बाल श्रम कहते हैं, जो उनके मौलिक अधिकारों के साथ ही उनके जीवन की सभावनाओं पर भी निपटा रहा है।

का भी निगल रहा है। बाल श्रम काइ सरल या सतही समस्या नहीं है। यह उस गंभीर सामाजिक विडबना का परिणाम है, जिसमें समाज, सरकार, उद्योग और व्यक्तिगत स्वार्थ की जटिलताएं आपस में उलझी हुई हैं। किसी भी बच्चे को

उसकी इच्छा के विरुद्ध काम पर लगाना, उसे शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल जैसी मूलभूत चीजों से दूर करना, सीधा-सीधा उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

भारतीय सर्विशान का अनुच्छेद-24 यह स्पष्ट करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारबाहे, खदान या अन्य खतरनाक कार्यालयस्थि नियोजित नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद छोटे-छोटे ढाबों, चाय की दुकानों, ईंट पट्टों या बनाने वाली कंपों, विड़ी, कांप, पारखाएँ और चूड़ी उद्योगों में काम करते मासूम बच्चों को देखना एक आम दृश्य है। बाल श्रम की वैशिक रिपोर्ट को देखें तो आईएलओ और यूनिसेफ की 2023 की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 16 करोड़ बच्चे बाल श्रमिक हैं, जिनमें से लगभग 8 करोड़ बच्चे खतरनाक

चोट अंगुली में, दोष पूरे शरीर को देते हहे



ਹਫੀਜ ਕਿਟਵੰਡ

लालू जेल में हैं, यह भी उनकी
ईमानदारी है। बहुत पहले लिखा था
कि राहुल को इस भारत में अगर आज
फिसी से राजनीतिक दीक्षा लेनी
चाहिए, वह सिर्फ़ लालू प्रसाद यादव हैं।
राहुल ने तो आगे बढ़कर लालू जी को
गले लगा लिया, उनके साथ देखकर
तबियत खिल उठती है। मैं खुद हमेशा
खुद को कोसता हूँ कि लालू को मापने
में हमने इतना अगर मार कर्यों किया।
कर्यों लालू को जांचने में हमने उनकी
सुनी जो अपनी जबाब कहीं किसी
शाखा से उधार लाए थे। लालू जी का
जन्मदिन है, हम इसका प्रायः चिट करते
हैं कि हमने उस समय मूँह नहीं खोला
जब खोलना चाहिए था। लालू का
सलाखों में जाना हमारा खुद का कैद हो
जाना था, एक ही तो आवाज थी, जो
बिना तराजू लिए खोली थी। बस खुशी
इतनी है कि लालू जी को हमने कभी
खलनायक नहीं माना।

और लाशों पर राजनीति नहीं करते, बस इतना काफी है, उक्त प्रति प्रेम के लिए, हाँ हम लालू से प्रेम करने लगे हैं। जम्मूदिन मुवारक, ईश्वर आपको सफलता, समझ, अंदाज़ और स्मृति आपके नीचे तक भी पहुँचाएंगे और आपको स्वरूप रखें। तो जस्ती आपका हमें उपहार है और विचारिक प्रतिबद्धता आपको दिखाया रास्ता है, यह दोनों हमेशा बने रहें, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

CROWN BUREAU

�ੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੈ।



निर्णल यानी

हमारे देश में जिनता अधिक धर्म का ढिंगोरा पीटा जा रहा है अधर्म भी उनती ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों से ऐसे मामलों में लगातार बढ़दी रही की जा रही है। खासतौर से जब से आसाराम, स्वामी चिंमयानंद, गुरुमी राम रहीम, स्वामी नित्यानन्द, दाती महाराज, रामपाल, आसाराम के कृपुत्र नारायण साहं, धीरानंद महाराज उत्तर शिवामुख द्विवेदी, राम शंकर तिवारी उर्फ स्वामी परमानंद व अशू भाई महाराज जैसे व्यवधू संतों व डेरा संचालकों से जुड़े मामले सामने आए व इनमें से कई को बलात्कार व यौन शोषण के मामले में जेल जाना पड़ा। तब से तो धर्म क्षेत्र में इस तरह के कुकर्मों की गोया झड़ी सी लग गई। देश में जाने किनते साथू वेश राहरा मरिद के पुजारीया कि किसी ने किसी रूप में धर्म क्षेत्र से जुड़े लोग यौन कारोबार के शर्मनाक मामलों में घटकड़े जा रुक्के हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दोपक वर्षमान नामक एक बलात्कारी को थाना आलखनवाग के अतर्गत पुलिस ने सूर्योदय से पूर्व ही सुवह चुभेर्डे में मार गिराया, यह व्यक्ति भी धर्म का चौला ओढ़े रहता था। स्वयं लाख का इनामी भी घोषित कर दिया था। उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फूटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की और गत वीवराव को देर रात थाना आलखनवाग क्षेत्र के मवेया के निकट एनकार्टर में ढेर कर दिया। भारत जैसे धर्म प्रधान देश में यौन शोषण के मामलों का तेजी से बढ़ता अव्याप्ति चिंता का विषय है। हालांकि देश में यौन शोषण को लेकर काफी कड़े बनी वाली हुए हैं फिर भी यह एक रूपरेखा समाजिक समस्या बनी हुई है। खासकर धर्म क्षेत्र में कुकर्मियों व अधर्मियों का प्रवेश कर जाना धार्मिक सीख व शिक्षाओं पर भी सवाल खड़े करता है।

एक अनुमान के अनुसार भारत में प्रत्येक 22 मिनट में एक बलात्कार का मामला दर्ज होता है। इसमें वह मामले शामिल नहीं हैं जो भयशब्द या लाज वाश अथवा सुलह सफाई के बाद या फिर सामाजिक कानून के बलात्कारी का कानून व्यवस्था के कारण दर्ज नहीं होते और वह सरकारी विप्राति ने तीन नाबालिग बहनों को काल सर्प दोष की पूजा करने के बहाव अपने कमरे में बुलाकर उनका बलात्कार किया। पीड़िता बहनों के परिजनों को शिकायत पर नादन थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया।

(प्राचीनकालीनाविकास)

बचपन की छिनती गुटकान: बाल श्रम मौलिक अधिकारों का हनन

विश्व बाल श्रग निषेध दिवस पर विशेष



અનુભૂતિ

के अनुसार, 2023 तक भारत में 5 से 14 वर्ष की आयु के लगभग 1.01 करोड़ बच्चे बाल श्रमिक हैं। हालांकि पिछले दो दशकों में शिक्षा के प्रचार, सरकारी योजनाओं और गैर-सरकारी संगठनों की महनत से बाल श्रमिकों को संख्या में गिरावट आई है, लेकिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटेहोंगे, घरेलू कामों और खेती-बाड़ी जैसे असंगठित क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति अब भी थोड़ी है। महामारी के बाद कोविड-19 के कारण परिवारों की अर्थर्थिक स्थिति खराब होने से कई बच्चों को पढ़ाई छोड़कर काम पर जाना पड़ा।

भारत के कई हिस्सों में बच्चों को आज भी पढ़ाई और खेल के बजाय दिनभर मजदूरी में ज़िक्र दिया जाता है। कभी-वे सङ्कट किनारे भी थी मार्गते, कचरा बीनते, जूते पालिश करते या काखानों में सस्ते विक्री की तरह इस्तमाल किए जाते हैं। बाल श्रम बच्चों को न केवल स्थिति के अधिकार से वर्चित करता है, बल्कि उन्हें स्थारिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर भी हानि पहुँचाता है। अस्वच्छ और खतरनाक वातावरण में काम करने के कारण बच्चों को सांसार की बीमारी, अस्थमा, त्वचा रोग, टीवी, रीढ़ की हड्डी के विकार और कैंसर तक हो सकता है। साथ ही लंबे समय तक

पोषण की कमी और शारीरिक शोषण के कारण वे उम्र से पहले बुढ़े दिखने लगते हैं और मानसिक रूप से भी अवसाद, डर, हीनता ग्राह्य और अपाराध की उनियाँ की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। यह समस्या सिफे मानवीय सकृत नहीं है, यह आर्थिक और सामाजिक विकास में भी बाधा है। एक समाज का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर करता है। यदि वह पीढ़ी शिक्षा के बजाय बचपन में ही मजदूरी करने लग जाए तो न केवल उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है बल्कि पूरे राष्ट्र की प्रगति भी अवरुद्ध हो जाती है। मानव संसाधन की क्षमता, उत्पादकता में गिरावट और सामाजिक कानून की प्रभावशीलता संदर्भ बनी हुई है क्योंकि निगरानी, प्रवर्तन और सज्जा की प्रक्रियाएँ अपेक्षित करने वाले मनजोर हैं। कई बार चच्चा परिवार की मदद के नाम पर घरेलू उद्योगों में कार्य करता रहता है और कानून इसकी सही से व्याप्त्या नहीं कर पाता। बाल त्रय से जुड़ी एक बड़ी विढ़ंबना यह भी है कि कई बार इन्हें बचाने वाले कानून ही इनके अधिकारों की राह में बाधा बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जब कानून में यह ग्राविधान है कि चच्चा परिवारिक काम कर सकता है तो इसका फायदा उठाकर बाल मजदूरी की परिवारिक रोजगार बताकर उसे वैध ठहराने की कोशिश की जाती है।

असमनाता जैसे दुष्प्रियणाम सामने आते हैं। बाल श्रम के पांडे अनेक कारण हैं लेकिन गरीबी इसकी सबसे मजबूत जड़ है। जब एक परिवार अपनी बुनियादी अवश्यकताओं भोजन, पानी, धन और शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाता तो बच्चे को स्कूल भेजने के बजाय काम पर भेज देना मजबूरी बन जाती है। इसके अलावा निरक्षरता, कुपोषण, किसी सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच का अभाव, बाल तस्करी और अज्ञानता भी बाल श्रम के प्रमुख कारक हैं। प्रामोग क्षेत्रों में अभिभावकों को यह तक पता नहीं होता कि उनके बच्चे को मजदूरी पर लगाना कानूनी अपराध है और सर्विधान उनके बच्चे को शिक्षा और सुरक्षित बचपन का अधिकार देता है। बाल श्रम को रोकने के लिए भारत में बाल श्रम (यथा और यथानिमन) अधिनियम 1986 बनाया गया था, जिसे 2016 में संशोधित कर और कठोर किया गया। इस संशोधन में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के किसी भी कार्य में नियोजन पर पूर्ण प्रतिवर्द्ध है, साथ ही 14-18 वर्ष के किशोरों को खत्तरनक उद्योगों में काम पर लगाने पर भी रोक लगाई गई है। इसके बावजूद इस

इसके अलावा असंगठित क्षेत्रों में, जहाँ निरीक्षण की व्यवस्था नहीं है, वहाँ तो स्थिति और भी भयावह होती है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जैसी योजनाएं भी चलाई हैं, जिनका उद्देश्य 9 से 14 वर्ष की आयु के बाल श्रमिकों को बचाकर उन्हें विशेष विकालांगों में दाखिल करना और उन्हें वृन्दावन सहायता देना है, ताकि इन योजनाओं का कार्यान्वयन और जमीनी असर आज भी सीमित और असमान है। कई जिलों में इनकी उपस्थिति नहीं है और जहाँ है भी, वहाँ संसाधनों और प्रशिक्षित मानवबल की कमी है। यदि भारत को सच में बाल श्रम मुक्त बनाना है तो केवल कानून बनाना या कुछ योजनाएं शुरू करना पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए व्यापक सामाजिक बदलाव की आवश्यकता है। सबसे पहले तो सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे मूलभूत क्षेत्रों को स्कूल भेजने में सक्षम बनें। साथ ही कौशल विकास कार्यक्रमों को मजबूत बनाकर युवाओं को रोजगार योग्य बनाना होगा।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

